प्रवाह
निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

पलायन चुनौतियां पेश करता है, पर मानव विकास बढ़ाने, अच्छे काम को बढ़ावा देने का मौका भी देता है...
- बान की मून

संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव

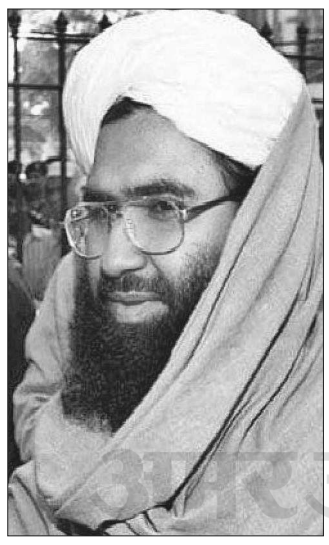

भारत को कूटनीतिक प्रयास के जरिये चीन को राजी करना चाहिए, ताकि अगले हफ्ते जब अमेरिका और ब्रिटेन के समर्थन से जैश सरगना को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किए जाने का फ्रांस का प्रस्ताव आए, तो उसे निर्णायक परिणति तक पहुंचाया जा सके।

निशाने पर मसूद अजहर

पुलवामा हमले के गुनहगार जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को लेकर भले ही पाकिस्तान से भ्रमित करने वाली खबरें आ रही हैं, लेकिन उसकी वहां मौजूदगी खुद पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी स्वीकार कर चुके हैं। सीआरपीएफ के काफिले पर किए गए फिदायीन हमले के बाद से भारत को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में लगातार अंतरराष्ट्रीय बिरादरी का समर्थन मिल रहा है, जिससे पाकिस्तान का परेशान होना स्वाभाविक है। पुलवामा हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तान के भीतर बालाकोट में स्थित जैश के आतंकी ठिकाने पर हमला किया था। पाकिस्तान ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बताने की कोशिश की, लेकिन उसे समर्थन नहीं मिला। इसके उलट संयुक्त राष्ट्र ने पुलवामा हमले की निंदा की और सुरक्षा परिषद के तीन स्थायी सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने मसूद अजहर को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने से संबंधित प्रस्ताव लाने का एलान कर दिया। इसके अलावा रूस ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन करने का भरोसा दिया है, जो इसलिए बड़ी सफलता है, क्योंकि रूस ने भारत के प्रयासों से इन्हीं तीन देशों द्वारा मसूद अजहर को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किए जाने के लिए 2016 और 2017 में लाए गए प्रयासों पर ठंडा रुख दिखाया था। मसूद अजहर को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किए जाने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा चीन है, जो पाकिस्तान का न केवल मित्र है, बल्कि जिसने उसके यहां अच्छा-खासा निवेश भी कर रखा है। तकरीबन एक दशक के दौरान भारत ने मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करवाने के प्रयास किए हैं, लेकिन हर बार चीन ने प्रस्ताव का विरोध कर इस पर पानी फेर दिया। लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग हैं, पाकिस्तान की उम्मीदों के विपरीत चीन ने पुलवामा हमले की निंदा की है। हाल ही में भारत, रूस और चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान परस्त आतंकवाद को लेकर मजबूती से अपना पक्ष रखा था। इसके बावजूद इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि चीन पाकिस्तान को भरोसे में लिए बगैर प्रस्ताव का समर्थन नहीं करेगा। ऐसे में भारत को सोच-समझकर कूटनीतिक प्रयास करने चाहिए, ताकि अगले हफ्ते जब मसूद अजहर को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किए जाने से संबंधित प्रस्ताव आए, तो उसे उसकी निर्णायक परिणति तक पहुंचाया जा सके।

विकास में बाधक है क्षेत्रीयता की भावना

पश्चिम में, ब्रेग्जिट और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप व हंगरी में विक्टर ओरबान जैसे दक्षिणपंथी लोकप्रिय नेताओं के उदय के लिए भूमंडलीकरण को दोषी ठहराया गया है। खासकर अनेक लोगों ने यह तर्क दिया है कि अनियंत्रित अंतरराष्ट्रीय प्रवास (जो भूमंडलीकरण का एक प्रमुख रूप है) ने स्वदेशी भावना से संबंधित विरोध को जन्म दिया है। विकासशील दुनिया लंबे समय से ऐसे विरोध की आदी रही है। हालांकि विकासशील देशों में क्षेत्रीय भावना से जुड़े इस विरोध का केंद्र अंतरराष्ट्रीय प्रवास के बजाय अक्सर दूसरे राज्यों से आए लोगों पर रहता है। भारत में इस तरह के संघर्ष के प्रमुख उदाहरणों में स्वदेशी या 'माटी के लाल' को लेकर मुंबई और असम की राजनीति है।

अपनी नई पुस्तक *नेटिविज्म ऐंड इकोनोमिक इंटिग्रेशन एक्रॉस द डेवलपिंग वर्ल्ड* में हमने विकासशील दुनिया में घरेलू पलायन के खिलाफ उपजे विरोध को रेखांकित किया है। विकासशील दुनिया में हर जगह आर्थिक विकास और एकीकरण आंतरिक या घरेलू पलायन के साथ हुआ है। यह पलायन उन जगहों पर मानव संसाधन लाता है, जहां उन्हें सबसे अधिक मूल्यवान माना जाता है। इसी के साथ पलायन और स्वाभाविक जनसंख्या वृद्धि आर्थिक प्रतिस्पर्धा बढ़ाती है और संसाधनों का खिंचाव उन जगहों पर होता है, जहां प्रवासी टिकते हैं। मुंबई में 'मूल' निवासियों ने इस तरह के विकास का अक्सर विरोध किया है। पलायन के कारण उन जगहों पर मूल निवासी की राजनीति होने की आशंका ज्यादा रहती है, जहां स्थानीय स्तर पर चुनाव रहते हैं। यह राजनेताओं को बाहरी लोगों के खिलाफ स्थानीय लोगों को परिभाषित करने और उन्हें विशेषाधिकार देने का कारण बनता है। विश्व बैंक जैसे अंतरराष्ट्रीय संस्थानों द्वारा आगे बढ़ाए गए राजनीतिक विकेंद्रीकरण ने उप-शासन के नए स्तरों का निर्माण किया है, जिस पर मूल निवासियों द्वारा आसानी से कब्जा जमाया जा सकता है।

एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन के खिलाफ गुस्सा दिखता है। पर घरेलू स्तर पर पलायन से आर्थिक विकास होता है।

रिखिल आर. भवनानी और बेथानी लासिना

कुछ समय पहले तक विद्वानों के पास घरेलू पलायन से संबंधित व्यवस्थित आंकड़े का अभाव था। अपने श्रमसाध्य कार्य के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया के कुछ विद्वानों की टीम ने 21 विकासशील देशों के लिए 'प्रवास का ढांचा' तैयार किया। हमने विभिन्न रूपों के स्वदेशीवाद और घरेलू प्रवास के बीच संबंध की जांच करने के लिए इन आंकड़ों का उपयोग किया। जैसा कि हमने अपनी पुस्तक में दिखाया है, घरेलू प्रवास लैटिन अमेरिका में 'स्वदेशी दलों' के उदय से जुड़ा है, जिसने विशेष रूप से भूमि पर स्वदेशी समुदायों की मांगों को जन्म दिया। आंकड़े बताते हैं कि 21 देशों के 526 क्षेत्रों में आंतरिक पलायन और घरेलू दंगे के बीच मजबूत सकारात्मक संबंध है। अगर हम अलग-अलग देशों के आंकड़ों को देखें, तो 21 देशों में से 18 देशों में आंतरिक प्रवास और दंगे सकारात्मक रूप से संबद्ध हैं। शेष दो देशों में दंगे नहीं हुए।

स्वदेशीवाद पर पलायन के प्रभाव की जांच में आम तौर पर दो तरह की समस्याएं सामने आती हैं। पहला, सामाजिक-आर्थिक अवसर जैसे आकलन कर पाने में कठिन कई तथ्यों को स्वदेशीवाद और प्रवास गंतव्य, दोनों से विश्लेषित किया जा सकता है। दूसरा, कार्य-कारण की दिशा उलट हो सकती है : अगर पलायन लोगों में अपने देश की भावना पैदा कर सकता है, तो स्वदेश की इस सोच से भी पलायन के पैटर्न को प्रभावित करने की संभावना है। इन समस्याओं से निपटने के लिए हम भारत में प्राकृतिक आपदा से प्रेरित पलायन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। बाढ़ और सूखे से पलायन को आश्चर्यजनक रूप से गति मिलती है। आंतरिक पलायन अक्सर प्रवासी-विरोधी राजनीति के उदय से जुड़ा होता है, क्योंकि पार्टियां मूल निवासी की भावनाओं को संतुष्ट करती हैं या नई पार्टियां ऐसी ही भावनाओं को संतुष्ट करने के लिए उभरती हैं। महाराष्ट्र में घरेलू पलायन ने शिवसेना के उदय को बढ़ावा दिया, जो 1970 के दशक तक दक्षिण भारतीय प्रवासियों के खिलाफ संघर्ष कर रही थी, फिर 1980 और 1990 के दशक में उसने अपना ध्यान मुस्लिम प्रवासियों पर केंद्रित किया और उसके बाद उसने उत्तर भारतीयों, खासकर बिहारियों को अपना निशाना बनाया। हमने पाया कि जब प्राकृतिक आपदाओं के कारण महाराष्ट्र के कुछ जिलों में प्रवासी पहुंचे, तो उन जिलों में बाद के चुनावों में शिवसेना के समर्थन की संभावना बढ़ गई।

भारत में स्थानीय सरकारें भी कथित मूल निवासियों का पक्ष लेती हैं और घरेलू प्रवासियों के साथ भेदभाव करती हैं। राज्य सरकारें राज्य से बाहर के कुछ ही प्रवासियों को नियुक्त करती हैं। भारत सरकार ने 1990 के दशक के प्रारंभ में बड़े पैमाने पर विकेंद्रीकरण सुधारों को लागू किया और 2,00,000 गांवों, तालुका और जिला स्तर पर स्थानीय सरकारों का गठन किया। तब से हर स्तर पर प्रतिस्पर्धी चुनाव होते हैं, राजनेताओं को अपने मतदाताओं को परिभाषित करने और उनकी मांगों को पूरा करने के लिए भारी चुनावी प्रलोभन देना पड़ता है। राज्य सरकारों ने विकेंद्रीकरण सुधारों के बाद कम घरेलू प्रवासियों को काम पर रखा।

आंतरिक प्रवास आर्थिक विकास के लिए सबसे सुरक्षित रास्तों में से एक है। जैसे-जैसे लोग उप-राष्ट्रीय सीमाओं को पार करते हैं, वे कहीं भी जाने की स्वतंत्रता के अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं और स्वयं में काफी सुधार करते हैं। ऐसे में, पलायन में बाधा डालने वाली क्षेत्रीयता की भावना घरेलू पलायन की संभावनाओं को ही कम कर देती है। सवाल यह है कि ऐसे में हम घरेलू पलायन की संभावनाओं को साकार करते हुए इसके खिलाफ उभरे विरोध को कैसे कम कर सकते हैं। केंद्र सरकार न केवल उन क्षेत्रों में, जहां लोग पहुंच रहे हैं, बल्कि उन क्षेत्रों में भी, जहां से लोग बाहर निकल रहे हैं, संसाधनों का पुनर्वितरण कर सकती हैं। इससे जहां बढ़ते पलायन से स्थानीय लोगों में आक्रोश नहीं होगा, वहीं पलायन पर भी अंकुश लगेगा। अन्य विद्वानों की तरह हमने भी यह पाया है कि भारत सरकार उन राज्यों को आवंटन देने के मामले में ज्यादा उदार है, जहां प्रधानमंत्री की सहयोगी पार्टियों की सरकारें हैं। अगर भारत सरकार राज्यों के बड़े गठबंधन से शक्ति हासिल करती है, तो आतंरिक पलायन की चुनौती का प्रबंधन करने की ज्यादा संभावना है।

रिखिल आर. भवनानी यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन-मैडिसन में और बेथानी लासिना यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर में एसोसिएट प्रोफेसर हैं।

अंतर्ध्वनि

>> फणीश्वरनाथ रेणु

उस वटवृक्ष को छोड़ अपनी कहानी लिखना असंभव

अपने संबंध में कुछ लिखने की बात मन में आते ही मन के पर्दे पर एक ही छवि 'फेड इन' हो जाया करती है : एक विशाल वटवृक्ष... ऋषि तुल्य, विराट वनस्पति! फिर, इस छवि के ऊपर 'सुपर इंपोज' होती है दूसरी तस्वीर : जटाजूटधारी बाबूजी की गोद में किलकता एक नन्हा शिशु!! और तब अपने बारे में कुछ लिखने की बात मन से दूर हो जाती है। क्योंकि इस वृक्ष को बाद देकर अपनी कहानी लिख पाना मेरे लिए असंभव है।

अतः जब लिखने बैठा हूं, शुरू में ही कबूल कर लेना ठीक है कि मैं कुसंस्कारों में पला अंधविश्वासी हूं। इसके अलावा क्या हो सकता था मैं? मेरे गांव के लोग, परिवार के लोग एक पेड़ को पूजते थे। गांव का प्रत्येक बच्चा उस 'पेड़-देवता' की कृपा से जीता था, उसके कोप से मरता था। सारे गांव के लोग, गांव से बाहर जाते और लौटते समय, कोई नया काम शुरू करने के पहले इस पेड़ को शीश नवाकर दंडवत करना नहीं भूलते थे। गांव से उत्तर, सड़क के किनारे, विशाल तरुवर के तले राही-बटोही और 'बनिजारे' गाड़ीवानों के दल सदा सुस्ताते। कभी विवाह और गौना की बरात गुजरती। दुलहिन की पालकी बरगद के नीचे रुकती। सारा गांव उमड़ पड़ता। लाल-लाल डोली से 'लाली-लाली दुलहिनियां' निकलकर, धरती पर माथा टेक-कर दंडवत करती। पालकी जब उठने लगती, गांव के बच्चे तालियां बजाकर एक स्वर से गाने लगते - 'लाली-लाली डोलिया में लाली रे दुलहिनियां...।' नन्ही दुलहिन कुछ वर्षों के बाद एक नवजात 'लड़िकनवां' लेकर लौटती। तब, एक बार फिर बट बाबा के पास टप्परवाली गाड़ी रुकती। छाती से अपने कलेजे के टुकड़े को सटाए, नई-नई हुई अल्हड़-सी मां गाड़ी से उतरती -'दुहाय बट बाबा !' बरगद की डालियों पर सदा दुनिया-भर की चिड़ियों का कलकूजन होता रहता।

-दिवंगत हिंदी उपन्यासकार

मंजिलें और भी हैं

>> सोमित श्रीवास्तव

कोशिशों से बदली केंद्रीय विद्यालयों की तस्वीर

जब मैं देहरादून संभाग में केंद्रीय विद्यालय संगठन का उपायुक्त बनकर गया था, तभी मैंने वहां की स्थिति सुधारने के बारे में सोच लिया था। देहरादून संभाग में कुल पैंतालीस केंद्रीय विद्यालय हैं। वहां के स्कूलों में शिक्षकों के पचास फीसदी पद अमूमन खाली रहते हैं, इसलिए रिजल्ट के मोर्चे पर यह संभाग बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा था। मैंने संभाग के सभी प्रिंसिपलों को रोज एक क्लास सुपरवाइज करने के लिए कहा। इतना ही नहीं, मैंने यह भी व्यवस्था भी की कि एक क्लास मॉनिटर करने के बाद वह उसकी रिपोर्ट उसी समय व्हाट्सएप पर सहायक आयुक्त को भेज देंगे, ताकि वास्तविक प्रगति के बारे में जाना जा सके। इससे पहले प्रिंसिपलों की रिपोर्ट सहायक आयुक्त तक पहुंचने में महीना-डेढ़ महीना लग जाता था, जिससे केवल खानापूर्ति ही होती थी। अब खुद प्रिंसिपल अपनी एक क्लास के बारे में सजग रहने लगे और सहायक आयुक्त भी समय पर रिपोर्ट न पहुंचने से संबंधित प्रिंसिपल से पूछने लगे। इससे देहरादून संभाग के सभी केंद्रीय विद्यालयों में एक किस्म की जिम्मेदारी की भावना आई। इसका नतीजा यह हुआ कि रिजल्ट के मामले में जो देहरादून संभाग कुल पच्चीस संभागों में आठवें नंबर पर आता था, वह तीसरे नंबर पर आ गया। देहरादून संभाग ने दक्षिण भारत के कई संभागों को पीछे छोड़ दिया। यह परिणाम चमत्कृत करने वाला था। इससे यह भी पता चला कि गंभीर कोशिश के अनुकूल परिणाम मिलते हैं।

मैंने स्थिति सुधारने के अलावा हर छात्र से रीयल टाइम फीडबैक लेने का तंत्र विकसित किया।

यही सुधार मैंने दूसरे क्षेत्र में भी शुरू किया। केंद्रीय विद्यालयों में कैंपस के बाहर की गतिविधियां बहुत अधिक होती हैं, जैसे खेल-कूद, यूथ पार्लियामेंट वगैरह-वगैरह। ऐसे आयोजनों में अलग-अलग संभाग से छात्र और शिक्षक आते हैं तथा एक कैंपस में ठहरते हैं। वैसे में उनके खाने-पीने से लेकर दूसरी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। अब तक अमूमन यही नजरिया अपनाया जाता था कि किसी तरह आयोजन हो जाएं। जैसे, खाने-पीने की व्यवस्था के लिए टेंडर जारी किए जाते थे, और सबसे कम खर्च में भोजन उपलब्ध करा देने वाले को टेंडर दे दिया जाता था। इससे भोजन की गुणवत्ता खराब रहती ही थी, छात्रों को पेट भर भोजन नहीं मिलता था और कई जगह बासी खाना परोसने की भी शिकायत मिलती थी। मैंने यह व्यवस्था बदली। जिस स्कूल में आयोजन तय होता, मैंने उस स्कूल के प्रिंसिपल को टीम बनाकर खाने-पीने का कच्चा माल खुद खरीदने के लिए कहा और सिर्फ ब्रांडेड सामान खरीदने की ही शर्त रखी। साथ ही, ठेकेदार को स्पष्ट निर्देश दिया कि बचा हुआ खाना किसी भी स्थिति में अगली बार इस्तेमाल नहीं होगा। छात्रों से फीडबैक लेने पर पता चला कि ऐसा भोजन उन्हें पहले कभी नहीं मिला था। और ब्रांडेड चीजें खरीदने के बावजूद लागत में पचास हजार से एक लाख रुपये तक की बचत हुई। सिर्फ भोजन नहीं, बाथरूम, डाइनिंग रूम और सोने की जगह गंदगी या अव्यवस्था को सुधारने के लिए भी मैंने कदम उठाए। मैंने एक तरफ स्थिति बेहतर करने की ओर ध्यान दिया, दूसरी ओर, हर छात्र से रीयल टाइम फीडबैक लेने का तंत्र विकसित किया। यानी किसी भी छात्र को किसी भी मामले में असुविधा हुई या अव्यवस्था दिखी, तो वह तत्काल इस बारे में सूचना दे सकता था।

कुछ महीने पहले मैं भोपाल संभाग में केंद्रीय विद्यालय संगठन का उपायुक्त बनकर आया हूं। यहां कुल साठ केंद्रीय विद्यालय हैं। यहां भी धीरे-धीरे सुधार कार्यों की मैंने शुरुआत की है।

परमाणु हथियारों का जोखिम

परमाणु हमला होने पर एक देश में करोड़ों लोग तो मारे ही जाएंगे, उसके पर्यावरणीय दुष्प्रभाव से दूसरे देशों में भी लोगों की मृत्यु होगी, क्योंकि आज के परमाणु बमों की विध्वंसक क्षमता हिरोशिमा-नागासाकी में गिराए गए बमों से डेढ़ लाख गुना अधिक है।

इस समय दुनिया में 15,000 से अधिक परमाणु हथियार हैं। इनमें से 90 प्रतिशत हथियार अमेरिका और रूस के पास हैं, जबकि शेष 10 फीसदी हथियार ब्रिटेन, फ्रांस, इस्राइल, चीन, पाकिस्तान, भारत और उत्तर कोरिया के पास हैं। अभी तक विश्व में दो परमाणु बमों का उपयोग हुआ है। ये दो बम अगस्त, 1945 में अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए गए थे। उन दो बमों से साढ़े तीन लाख लोगों की मौत हुई थी। उनमें से बहुत से लोग भीषण रूप से जल गए थे और उनके जलते शरीर से त्वचा उतर रही थी। लोहे को पिघलाने के लिए जो तापमान चाहिए, उन बमों के गिरने के केंद्रीय क्षेत्र में उससे दोगुना तापमान हो गया था।

आज विश्व में जो 15,000 परमाणु बम हैं, उनमें से अधिकांश हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बमों से कहीं अधिक विध्वंसक हैं। परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए गठित आयोग ने दिसंबर, 2009 में जारी अपनी रिपोर्ट में बताया है कि आज दुनिया में जो परमाणु हथियार मौजूद हैं, उनकी विध्वंसक क्षमता हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से डेढ़ लाख गुना ज्यादा है। आयोग ने यह भी बताया है कि अमेरिका और रूस के पास अधिकांश परमाणु हथियार ऐसे हैं, जो बेहद खतरनाक स्थिति में तैनात हैं और मात्र चार मिनट में ये परमाणु हथियार दागे जा सकते हैं। आयोग का कहना है कि जब तक कुछ देशों के पास परमाणु हथियार हैं, तब तक अनेक अन्य देश भी उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करेंगे।

भारत डोगरा

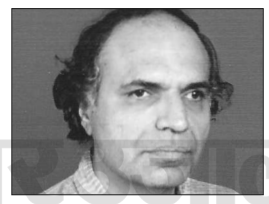

मानवीय विकास रिपोर्ट, 1997 के अनुसार, इस समय परमाणु हथियारों के भंडार की विनाशक शक्ति 20 वीं शताब्दी के तीन सबसे बड़े युद्धों के कुल विस्फोटकों की शक्ति से सात सौ गुना अधिक है। *टाइम* पत्रिका ने लिखा है कि आतंकवादी गिरोह भी ऐसे कामचलाऊ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे एक लाख तक लोग मारे जा सकें, खासकर तब, जब उन्हें किसी विदेशी सरकार का समर्थन प्राप्त हो जाए।

हिरोशिमा में जो बम गिराया गया था, उसकी तुलना में हाइड्रोजन बम को कई सौ गुना अधिक विध्वंसक बताया जा रहा है। दूसरी ओर, टैक्टिकल परमाणु हथियार नाम से कम विध्वंसक क्षमता के ऐसे परमाणु हथियार भी बनाए जा रहे हैं, जिनका उपयोग रणक्षेत्र में करने की अधिक आशंका हो। लेकिन अधिकांश विश्लेषक यह मानते हैं कि इनका उपयोग भी शीघ्र ही इससे बड़े परमाणु हथियारों की ओर ही ले जाएगा। जब पाकिस्तान के कुछ अधिकारियों ने कहा कि भारत के सैन्य हमले को वे टैक्टिकल परमाणु हथियारों से रोक देंगे, तो वहां के एक वैज्ञानिक ने समझाया कि इससे पाकिस्तान के अपने पर्यावरण व लोगों को भी बहुत भारी क्षति हो सकती है।

एरिक क्लासर परमाणु हथियारों के विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने *कमांड ऐंड कंट्रोल* नामक पुस्तक लिखी है। उन्होंने अनेक अध्ययनों के आधार पर बताया है कि परमाणु हथियारों का बड़ा युद्ध हुआ, तो एक ओर करोड़ों मारे जाएंगे, तो दूसरी तरफ उससे भी अधिक लोग दीर्घकालीन पर्यावरणीय दुष्परिणामों से अन्य देशों में भी मारे जाएंगे व सभी तरह का जीवन बुरी तरह तबाह हो जाएगा। भारत-पाकिस्तान में परमाणु युद्ध होने पर ऐसा होगा। अमेरिका और रूस में परमाणु युद्ध हुआ, तो इसकी तबाही और भी अवर्णनीय है। अतः किसी भी हालत में परमाणु हथियारों का उपयोग न हो और इन हथियारों को शीघ्र से शीघ्र धरती से हटाया जाए, इसे प्राथमिकता बनाने की जरूरत है।

खुली खिड़की

संगीत से कमाई

संगीत जीवन को आत्मिक शांति प्रदान करता है और उससे कमाई भी होती है। पिछले वर्ष सबसे ज्यादा कमाई आयरिश रॉक बैंड यू2 ने की।

सत्संग

मौका दोबारा नहीं मिलता

एक युवा एक फकीर के पास उसकी बेहद सुंदर लड़की का हाथ मांगने गया। फकीर ने कहा, तुम मेरी बेटी के योग्य हो या नहीं, यह परखने के लिए मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। तुम मेरे खेत में जाकर खड़े हो जाओ। मैं अपने घर से एक के बाद एक तीन बैल छोड़ूंगा। तुम्हें उनमें से किसी एक बैल की पूंछ पकड़नी है। यही तुम्हारी परीक्षा है। युवक इसके लिए खुशी-खुशी तैयार हो गया। वह बैल की पूंछ पकड़ने के लिए खेत में जाकर खड़ा हो गया। थोड़ी ही देर में फकीर के घर से पहला बैल तेजी से भागते हुए खेत में पहुंचा। लेकिन वह बेहद हट्टा-कट्टा और खतरनाक था। युवक उसे देखकर डर गया। उसने सोचा, कोई बात नहीं, अगले बैल की पूंछ पकड़ लेनी है। पर अगला बैल तो और भी तगड़ा और खूंखार था। युवक ने उसे भी जाने दिया और ठान लिया कि अगला बैल अगर इससे भी खूंखार निकला, तो भी वह जान की बाजी लगा। अब वह थोड़ा आगे खड़ा हो गया, ताकि अगले बैल के आते ही उसकी पूंछ पकड़ सके। आखिरी बैल को फकीर के घर से निकलते देख वह खुश हो गया। वह बैल बेहद दुबला और मरियल था और धीरे-धीरे आ रहा था। युवक तेजी से बैल की ओर लपका। पर इस बैल की तो पूंछ ही नहीं था। यह देख वह बेहद निराश हो गया। तभी उसे वह फकीर दिखा, जो उससे कह रहा था, अगर एक बार अवसर गंवा दिया, तो मौका दोबारा नहीं मिलता।

-संकलित

हरियाली और रास्ता

रोहन और वह गरीब बच्चा

एक गरीब बच्चे की कहानी, जिससे रोहन को भलाई करने की प्रेरणा मिली।

रोहन और स्मिता बाजार घूमने गए थे। स्मिता शांत स्वभाव की थी, जबकि रोहन भावनाओं में बह जाने वालों में से था। बाजार में खूब चहल-पहल थी। तभी एक बच्चे ने पीछे से स्मिता का कुर्ता खींचते हुए उससे कुछ पैसे मांगे। स्मिता डर गई। स्मिता को डरा देख रोहन भी हैरान हो गया। उसने देखा, उस बच्चे का एक हाथ नहीं था। स्मिता उसे डांटने लगी, तुम लोगों को मैं अच्छी तरह से जानती हूं। भीख मांगने का यह कोई तरीका है? वह बच्चा स्मिता के तेवर देख सहमकर पीछे हट गया। रोहन ने स्मिता से कहा, छोड़ो न, बेचारा गरीब है। स्मिता बोली, इससे पूछो, अगर इसे पैसे चाहिए, तो कोई काम क्यों नहीं करता? रोहन बोला, बेचारे का एक हाथ नहीं है। पता नहीं, इसके घर के क्या हालात होंगे। रोहन ने उस बच्चे को अपने पास बुलाकर कहा, एक काम करो, इस चाय की दुकान के आसपास जितने कप पड़े हैं, सबको इकट्ठा कर कूड़ेदान में फेंक दो। हम तुम्हें पैसे देंगे और अपनी गाड़ी से घर भी छोड़ेंगे। बच्चे की आंखें चमक उठीं। उसने फटाफट वहां पड़े सारे कप इकट्ठा कर लिए और उन्हें कूड़ेदान में फेंक दिया। रोहन ने उस बच्चे को कुछ पैसे दिए। अब वह स्मिता के साथ उस बच्चे को उसके घर छोड़ने जा रहा था। रोहन ने पूछा, तुम्हारा घर कहां है? बच्चा बोला, वह जो नई-नई बिल्डिंग बन रही है न, उसी में।

रोहन बोला, लेकिन यह तो सुलभ शौचालय है। तुम यहां रहते हो? बच्चा बोला, नहीं, बस इसके पीछे की तरफ मां ने एक छप्पर लगा रखा है। रोहन ने देखा कि उस बच्चे की मां बीमार थी और कई दिनों से काम पर नहीं गई थी। इस वजह से बच्चे को भीख मांगनी पड़ रही थी। रोहन ने स्मिता से कहा, हमें गरीब और मजबूर लोगों की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए।

हकीकत जाने बगैर कभी किसी के बारे में राय नहीं बनानी चाहिए।